

>

Title : Need to regularize the services of 'Shikshamitra' in primary schools of the country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के अंदर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सभी प्रदेशों में की गयी है। आज उनके सामने बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। तमाम प्रदेश - चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो और अन्य राज्यों में भी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुयी है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में उनको केवल मानदेय मिलता है। उनसे बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करने के लिए कहा जाता है, वे पूरी तरीके से पढ़ाई भी कराते हैं। अन्य राज्यों ने उन्हें स्थायी कर्मचारी घोषित करते हुए, उनके बराबर वेतन देने की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में, जो शिक्षा मित्रों को मानदेय दे रहे हैं, उनको स्थायी कर्मचारी नियुक्त करके, कम से कम जो शिक्षक प्राइमरी या जूनियर विद्यालय में हैं, उनको भी उसके बराबर वेतन दिया जाए। ...**(व्यवधान)** लालू जी कह रहे थे कि यह बिहार में भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनको स्थायी कर्मचारी घोषित करते हुए जैसे अन्य राज्यों ने अपने यहां व्यवस्था की है, उसी तरह उन्हें भी प्राइमरी या जूनियर अध्यापक के बराबर वेतन देने की व्यवस्था करें।

मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश करें और अगर बजट की व्यवस्था न हो, तो केंद्र सरकार राज्यों को बजट देकर उनको स्थायी कर्मचारी घोषित कर उसके बराबर वेतन दें, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। उनका बच्चों को पढ़ाने में मन भी लगे और वे बच्चों को पढ़ा सकें।